सलाहकारी संरचनाएँ

दो शीर्ष स्तर की समितियाँ अर्थात वैज्ञानिक सलाहकार समिति (सैक डीबीटी) तथा स्थाई सलाहकार समिति विदेश (सैक ओ) विभाग के चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा करने में सहायता देती हैं और नए तथा उभरते हुए क्षेत्रों, जिनके लिए सहायता की आवश्यकता है, का सुझाव देती हैं तथा साथ ही साथ नीतिगत मामलों पर सलाह देती हैं। सैक (ओ) विभाग के डीबीटी स्वायत्त संस्थानों की स्थापना और विकास करने के लिए मार्गनिर्देशों और परिदृश्य को प्रदान करने और औद्योगिकी क्षेत्र के विकास में शामिल है। सैक (ओ) की बैठकों या एक से एक अन्योय क्रिया के दौरान यह युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान के क्षेत्रों में सलाह देती है।

जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान व प्रौन्नति समिति कार्यदलों द्वारा सिफारिश किए गए 1 करोड़ रूपये या उससे अधिक बजट वाले प्रमुख कार्यक्रमों के वित्तपोषण के बारे में सिफारशें करती है और उनकी समीक्षा करती है। 18 कार्यदल वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए विभाग की सहायता करते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रस्तावों की समीक्षा करने, निगरानी करने और सिफारिश करने के लिए विशेष कार्यक्रम परिचालन समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न सलाहकारी संरचनाओं के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

2.1 वैज्ञानिक सलाहकार समिति

समिति एक शीर्ष सलाहकार निकाय है जिसमें विशेषज्ञ, वैज्ञानिक विभागो/एजेंसियों के अध्यक्ष और कार्यदलों के अध्यक्ष होते हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति (सैक डीबीटी) की 15वीं बैठक फरवरी, 2004 में आयोजित की गई। उभरते हुए क्षेत्रों पर विचार विमर्श के अलावा, बैठक ने आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों से जुड़े हुए विनियमिक प्रक्रियाओं को ठीक बनाने से संबधित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया। सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। समिति ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संस्थानिकीकरण के लिए संरचनाओं और प्रक्रियाओं के विकास और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, भविष्य की योजनाओं और अंतरमंत्रालयीय अन्योय क्रियाओं के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में शामिल पेटेंटिंग गतिविधियों पर भी सलाह दी। अगली बैठक वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान आयोजित की जाएगी।

2.2 स्थायी सलाहकार समिति विदेश

विभाग की, विदेश में रहने वाले अप्रवासीय भारतीयों वाली, विदेश स्थायी सलाहकार समिति सैक (ओ) माननीय राज्यमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार) की स्वीकृति के साथ पुनर्गठन किया गया है। स्थायी सलाहकार समिति विदेश सैक (ओ) की 15वीं बैठक 1819 फरवरी, 2005 को आयोजित की गई। उन क्षेत्रों, जिनमें विभाग प्रमुख वैज्ञानिक निवेश करने पर विचार कर रहा है, पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

स्टेम सेल अनुसंधान, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, कैंसर जीवविज्ञान, पादप और कृषि जीवविज्ञान, जैवसूचनाप्रणाली और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इन क्षेत्रों में विद्यमान शक्ति और उपलब्ध उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया और इन क्षेत्रों के और आगे विकास के लिए भविष्य के रोड मैपों पर विचार किया गया। प्रमुख सिफारिशों में नैदानिकी , औषध विकास , ऊतक इंजीनियरिंग आदि के लिए बहुसंस्थानिक कार्यक्रम शामिल है। मानव संसाधन विकास के लिए यह सुझाव दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालयों और पोस्टग्रेजुएट तथा डॉक्टरल स्तरों के विद्यार्थियों दोनों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालय आधारित अनुसंधान को सहायता और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात की आवश्यकता भी है कि उपलब्धियों से उत्पादों तक के विकास के लिए बैंच से बैड साइड तक ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए फिजिसियन वैज्ञानिकों के विकास की भी आवश्यकता है। समिति ने यह जैवसूचनाप्रणाली में जैववैज्ञानिकों को सक्रिय रूप से शामिल करने और आधुनिक जीवविज्ञान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में विषय की शुरूआत करने की वकालत की। अच्छे पादप जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम, विशेषतौर पर अजीविय और जीविय प्रतिबलों और पोषकता की जैवपुष्टीकरण के लिए पराजीनियों के विकास की ओर, के विकास के लिए पादप अणु जीवविज्ञान में अनुसंधान के स्तर में सुधार करने के लिए देश में कृषि जैवप्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव दिए गए। सामान्य जनस्तर पर सुधार करने और शिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए सुझाव दिया गया। स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय सेल लाइन आधान की स्थापना करने को महत्वपूर्ण माना गया जिससे मूलभूत शोधकर्ताओं और

चिकित्सकों को शामिल करके स्टेम सेल अनुप्रयोग गतिविधियों में वृद्धि हो सके।

2.3 जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रोन्नति समिति

एक करोड़ से ऊपर के बजट वाले बहुसांस्थानिक परियोजनाओं पर विचार करने के लिए समिति ने वर्ष के दौरान दो बैठकों का आयोजन किया। स्टेम सेल, मानव आनुवंशिकी, पर्यावरण, जलकृषि और समुद्री जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रमों पर विचार किया गया और सिफारिश की गई। संरचनात्मक और क्रियात्मक जीनोमिक्स के लिए इंटरनेशलन सोलानासी जीनोम इनीशियेटिव में भारत की भागीदारी को भी वीआरपीसी द्वारा स्वीकृत किया गया। चिकित्सीय प्रोटियोमिक्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और माइक्रोऐरे पर प्रमुख अवसंरचना सुविधाओं की सिफारिश की गई।

2.4 कार्यदल और अन्य विशेषज्ञ समितियां

विभाग के 18 कार्यदलों और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों/परिचालन समितियों की वर्ष के दौरान 2 से 4 तक बैठके हुई। उनमें वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किए गए नए प्रस्तावों पर विचार किया गया और साथ ही साथ पहले से ही वित्तपोषित चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

2.5 राष्ट्रीय जैवनीतिशास्त्र समिति

वर्ष के दौरान, जनवरी और अक्तूबर, 2004 में राष्ट्रीय जैवनीतिशास्त्र समिति की दो बैठके हुईं। समिति ने मानव आनुवंशिकी ब्यौरे पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पर यूनेस्को के मसौदे और साथ ही साथ

अंतिम दस्तावेज पर विचार विमर्श किया। उपयुक्त सुझाव दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के लिए कार्यान्वयन के भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई योजना के मसौदे दस्तावेज पर भी विचार विमर्श किया गया और उपयुक्त संशोधन किए गए। समिति ने जैवनीतिशास्त्र पर सार्वभौमिक मानकों पर घोषणा के दस्तावेज पर भी विचार विमर्श किया और सुझाव दिए।